



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 6, 2018/ज्येष्ठ 16, 1940

No. 215]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 6, 2018/JYAISTHA 16, 1940

आंध्रा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

[कार्मिक विभाग (आईआर)]

(प्रधान कार्यालय)

बधिसूचना

हैदराबाद, 8 मई, 2018

सं. 666/3/20/आईआर/27.—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1970 का 40) की धारा 19 और 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आन्ध्रा बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 में आगे संशोधन हेतु एतद्द्वारा दद्विम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

- (1) इन विनियमों को आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाएगा ।
- (2) इन विनियमों में जहाँ कहीं भी वर्णन किया गया है उसको छोड़कर, ये विनियम 1 नवम्बर, 2007 से प्रभावी माने जाएंगे ।
2. आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 (इसके बाद उक्त विनियम के रूप में संदर्भित होगा) के विनियम 3 में –
 - (i) खंड (च) हेतु निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् :-

(च) “परिवार” का अर्थ अधिकारी का जीवनसाथी, पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें आश्रित सौतेला तथा कानूनन गोद लिए गए बच्चे शामिल हैं), चालीस प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन और माता-पिता जो सामान्यतया अधिकारी के साथ रहते हैं और उन पर पूर्णतया आश्रित हैं ।

स्पष्टीकरण :- इस खण्ड का प्रयोजन अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित बच्चे या माता-पिता या शारीरिक रूप से विकलांग भाई या बहन का अर्थ उन बच्चों या माता-पिता, भाई या बहन से है जिनकी आय प्रतिमाह रु 3,500/- से अधिक नहीं है ।

किन्तु, यदि माता-पिता में से किसी एक की आय रु 3,500/- प्रतिमाह से अधिक है या माता-पिता दोनों की समग्र आय रु 3,500/- प्रतिमाह से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माना जाएगा।

(ii) खंड (ण) को हटा दिया जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में,

(i) उप विनियम (4ए) को हटा दिया जाएगा;

(ii) उप विनियम (4ए) को हटाने के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् –

“(5) नीचे दिए गए प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान 01 नवम्बर, 2007 से लागू होंगे :

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = रु 46800 – 1300/4 – 52000

वेतनमान VI = रु 42000 – 1200/4 – 46800

(ख) वरिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी

वेतनमान V = रु 36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 – 40400

वेतनमान IV = रु 30600 – 900/4 – 34200 – 1000/2 – 36200

(ग) मध्य प्रबन्धन श्रेणी

वेतनमान III = रु 25700 – 800/5 – 29700 – 900/2 – 31500

वेतनमान II = रु 19400 – 700/1 – 20100 – 800/10 – 28100

(घ) कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी

वेतनमान I = रु 14500 – 600/7 – 18700 – 700/2 – 20100 – 800/7 – 25700

स्पष्टीकरण – दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी का नियमन 01 नवम्बर, 2007 को इस उप विनियम में निर्धारित वेतनमान में प्रक्रम-दर-प्रक्रम आधार पर किया जाएगा, अर्थात् पहले प्रक्रम से तदनुसूची प्रक्रमों पर और वेतनवृद्धियों, अन्यथा उप बंधित को छोड़कर, सामान्यतया अधिवर्षिता तिथि को होगी।

(6) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में, -

(क) उप-विनियम (1) हेतु निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् –

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अधीन, दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को और उस तिथि से, वेतनवृद्धियाँ निम्नानुसार मंजूर की जाएंगी, अर्थात् -

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (5) में उपवर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियाँ, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर उपचय होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तिथि को दी जाएंगी;

(ख) जो अधिकारी कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में उच्च स्तर तक पहुँचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II की वेतनमान श्रेणी में पहुँच गए हैं वे प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए चार गतिरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो प्रत्येक रु 800/- और अगले दो प्रत्येक रु 900/- होंगे :

परन्तु, जो अधिकारी दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद तीन वर्ष या उससे अधिक का समय पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि दी जाएगी और अन्य कोई गतिरोध वेतनवृद्धि दिनांक 01 नवम्बर, 2008 को या उसके बाद दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात उनके छः वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी :

(ग) जो अधिकारी मध्य प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान II में उच्च स्तर तक पहुँचने के बाद मध्य प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान III की वेतनमान श्रेणी में पहुँच गए हैं वे प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए रु 900 की तीन गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

परन्तु, जो अधिकारी दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को पहली गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद तीन वर्ष या उससे अधिक का समय पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें अगली गतिरोध वेतनवृद्धि दिनांक 01 नवम्बर, 2007 से प्रभावी होने के साथ दी जाएगी और दिनांक 01 नवम्बर, 2008 को या इसके बाद आगामी गतिरोध वेतनवृद्धि पहली गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात उनके छः वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह भी कि मूल मध्य प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान III में नियुक्त या पदोन्नत अधिकारी प्रत्येक तीन पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए रु 900 की चार गतिरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे :

परन्तु, जो अधिकारी दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के पश्चात पहले से ही दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति तथा सेवा के तीन वर्ष या उससे अधिक का समय पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें तीसरी गतिरोध वेतनवृद्धि दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को प्रदान की जाएगी और दिनांक 01 नवम्बर, 2008 को या इसके बाद चौथी गतिरोध वेतनवृद्धि दूसरी गतिरोध वेतनवृद्धि की प्राप्ति के बाद उनके छः वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान की जाएगी ।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धि को पदोन्नति नहीं मानी जाएगी और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियाँ, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उनके मूल पदों के रूप में जारी रहेंगी ।

(ख) उप-विनियम (2) में, -

(i) स्पष्टीकरण (ड) के बाद और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात :-

“(च) दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को तथा उसके बाद से, अन्य बातों के समान होने पर, व्यवसायिक अर्हता वेतन की मात्रा निम्नानुसार संशोधित होगी :-

तालिका

जिन्होंने जे.ए.आई.आई.बी. अथवा सी.ए.आई.आई.बी. उत्तीर्ण कर लिए हैं ।	(i) अधिकतम स्केल तक पहुँचने के एक वर्ष बाद प्रति माह रु 410/-
जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं ।	(i) अधिकतम स्केल तक पहुँचने के एक वर्ष बाद प्रति माह रु 410/- (ii) अधिकतम स्केल तक पहुँचने के दो वर्ष बाद प्रति माह रु 1030/-

परन्तु, यदि किसी अधिकारी ने वेतन के अधिकतम स्केल तक पहुँचने के पश्चात जे.ए.आई.आई.बी. अथवा सी.ए.आई.आई.बी. (या तो कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त कर ली है तो उसे इस तरह की योग्यता प्राप्त करने की तिथि से व्यवसायिक अर्हता वेतन की पहली किस्त दी जाएगी और व्यवसायिक अर्हता वेतन के पश्चात जारी किस्त व्यवसायिक अर्हता वेतन की पहली किस्त जारी होने की तिथि के संदर्भ में होगी ।

परन्तु यह भी कि ऐसे मामलों में जहाँ किसी अधिकारी ने उपरोक्त योग्यता में से कोई एक पहले ही प्राप्त कर ली है और इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई वेतनवृद्धि या व्यवसायिक अर्हता वेतन नहीं लिया है, तो उसे दिनांक 01 नवंबर 2007 से प्रभावी या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद में है, से व्यवसायिक अर्हता वेतन प्रदान किया जा सकता है ।

(ii) टिप्पणी में, खंड (V) हेतु, निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

(V) यदि किसी अधिकारी ने, दिनांक 27 अप्रैल, 2010 को उक्त योग्यता में से कोई एक, जैसा कि खंड (iv) में विनिर्दिष्ट है, पहले ही प्राप्त कर ली है और इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के कारण कोई वेतनवृद्धि या व्यवसायिक अर्हता वेतन नहीं लिया है, तो उसे दिनांक 01 नवंबर, 2007 से प्रभावी या ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद में है, से व्यवसायिक अर्हता वेतन प्रदान किया जाएगा ।”

(ग) उप-विनियम (3) में,

- (i) खण्ड (घ) के बाद और टिप्पणी के पहले, निम्नलिखित खण्ड को जोड़ा जाएगा, अर्थात :-
(ड) 01 नवम्बर को तथा उसके बाद से 2007, अन्य बातों के समान रहने पर, आवास किराया भत्ते के साथ नियत वैयक्तिक वेतन निम्न दरों पर होगा और सेवा की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रभावी होगा :-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (रु)	वेतन वृद्धि घटकों पर 01.11.2007 को महंगाई भत्ते (रु)	कुल नियत वैयक्तिगत वेतन देय जहां बैंक का आवास प्रदान किया गया है (रु)
(क)	(ख)	(ग)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394

- (ii) टिप्पणी में, खण्ड (i) और (ii) के लिए, निम्नलिखित खण्डों को दर्ज किया जाएगा, अर्थात :-
- (i) नियत वैयक्तिक भत्ते अथवा नियत वैयक्तिक वेतन जैसा कि खण्ड (ख), (ग), लिका के के तहत ता (ड) या (घ) के रूप में निर्दिष्ट है (ग) स्तम्भ, उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक के साथ आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।
- (ii) आवास किराए भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ते अथवा नियत वैयक्तिक वेतन खण्ड (ड) के तहत तालिका के स्तम्भ (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट कुल राशि होगी और सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लिए गए आवास किराए भत्ते जहां विनियम 4 के उप-विनियमों (2), (3), (4) या (5) में विनिर्दिष्ट वेतन के सम्बन्धित स्केल की अन्तिम वृद्धि अर्जित की जाती है।
- (iii) टिप्पणी के बाद आने वाले खण्ड (खण्ड-के उप (ड)V) के लिए जैसा कि अंकित किया गया है, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
(V) “जिस अधिकारी को उपर्युक्त खण्ड के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि मिल चुकी है उसे उपर्युक्त (क) खण्ड (ख), (ग), नियत वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा/में उल्लेखित नियत वैयक्तिक भत्ते (ड) या (घ), वेतनमान के अधिकतम पहुँचने के एक वर्ष पश्चात होगी। “

5. उक्त विनियमों के विनियम में 21,

- (i) उप-विनियम (3) में, टिप्पणी को हटा दिया जाएगा;
(ii) उप-विनियम (4) में, टिप्पणी को हटा दिया जाएगा;
(iv) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों और टिप्पणियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात;

“(5) 01 नवम्बर 2007 को या उसके बाद से, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार पर 1960+100 के तिमाही औसत में 2838 अंकों से अधिक प्रति 04 अंकों के उतार या चढ़ाव के लिए महंगाई भत्ता वेतन का 0.15% देय होगा।”

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए,

(क) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु का अर्थ अवरोध वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन होगा। “वेतन”

(ख) विनियम) के उप विनियम 52(ग) के स्पष्टीकरण (, (घ) , में विनिर्दिष्टानुसार (च) और (ड) , व्यावसायिक अहर्ता भत्ते या व्यावसायिक अहर्ता वेतन को महंगाई भत्ते के लिए गिना जाएगा ।

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) और (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थगित किया जाएगा, अर्थात:-

(1) 01 नवम्बर 2002 को या उसके बाद से,

(क) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 1.75% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;

(ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात :

तालिका

जहां कार्यस्थल है	मकान किराया भत्ता देय होगा
(1)	(2)
(i) वर्ग 'ए' में प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहरों और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	वेतन का 8.5%
(ii) वर्ग 'बी' में क्षेत्र -I और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में अन्य स्थानों में	वेतन का 7.5%
(iii) अन्य स्थानों में	वेतन का 6.5%

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है, उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से अधिक, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया ऊपर स्तम्भ (2) के उल्लिखित पूर्वोक्त दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा ।

(1) 01 नवम्बर 2007 को या उसके बाद से,

वेतनमान में है यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे वह जिस (क) 1 उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 20% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;

यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान (ख) होगा किराया भत्ता पाने का पात्र, अर्थात :

तालिका

जहां कार्यस्थल है	मकान किराया भत्ता देय होगा
(1)	(2)
(iv) वर्ग 'ए' में प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहरों और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में	वेतन का 8.5%
(v) वर्ग 'बी' में क्षेत्र -I और परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में अन्य स्थानों में	वेतन का 7.5%
(vi) अन्य स्थानों में	वेतन का 6.5%

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है, उसके प्रथम प्रक्रम के 1.75% से अधिक, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया उपर स्तम्भ (2) के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150% देय होगा ।

टिप्पणी :-“अपने स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े हुए मकान किराए भत्ते हेतु अधिकारियों के दावे अब किराए भत्ते के 150% तक ही सीमित होंगे। “

7 उक्त विनियमों के विनियम 23 में,

- (i) उप विनियम (1) में, आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए 01 नवम्बर 2002 को 01 नवम्बर 2007 के आंकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप विनियम (2) में, आंकड़ों, पत्रों और शब्दों के लिए 01 नवम्बर 2002 को 01 नवम्बर 2007 के आंकड़ों, पत्रों और शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) उप विनियम (3), (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

“(3) 01 नवम्बर 2007 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी ग्रुप ए या ग्रुप बी की किसी परियोजना क्षेत्र में सेवारत हैं तो, वह निर्धारित ग्रुप ‘ए’ या ग्रुप ‘बी’ में क्रमशः रु 290 प्रतिमाह या रु255 प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।

“(4) 01 नवम्बर 2007 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का स्थानान्तरण किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाता है और यदि पूर्ववर्ती स्थान पर उसके एक या अधिक बच्चे स्कूल अथवा कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो उसे दूसरे स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अन्त तक सभी बच्चों के लिए रु 700/- प्रति माह का मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानान्तरण भत्ता देय होगा, परन्तु पूर्ववर्ती स्थान में सभी बच्चों द्वारा अध्ययन समाप्त करने पर उस भत्ते का भुगतान स्वतः समाप्त हो जाएगा।

“(5) 01 मई 2010 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन सभी परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है, विकल्पतः वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75% अधिकतम रु2300/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते हैं।”

परन्तु, यदि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु1200/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

परन्तु, यह भी कि जिस अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु1200/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

(IV) उप विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“(8) 01 नवम्बर 2007 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का एक दिन का कार्य समय दो घण्टों के न्यूनतम अन्तराल के साथ विभाजित होता है तो वह रु165/- प्रतिमाह की दर से विभाजित ड्यूटी भत्ते का पात्र होगा।”

(V) उप-विनियम (10) –

(क) आंकड़ों, पत्रों, तथा शब्दों हेतु “1 नवंबर 2002” को “1 नवंबर 2007” के आंकड़ों, पत्रों तथा शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) तालिका हेतु, निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर तथा उससे अधिक किंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान तथा मरकारा शहर	वेतन का 2% अधिकतम रु 550/- प्रतिमाह
(ii) 1500 मीटर तथा उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2½ % अधिकतम रु 680/- प्रतिमाह
(iii) 3000 मीटर तथा उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु 1570/- प्रतिमाह

8. उक्त विनियमों के विनियम 24 में, खंड (क) हेतु उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(क) चिकित्सा सहायता - 1 नवंबर, 2007 को तथा उसके बाद से अधिकारी अपने एवं परिवार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट राशि हेतु पात्र होगा। यह प्रतिपूर्ति अधिकारी द्वारा दिए गए स्वयं के प्रमाण पत्र में उल्लेखित व्यय विवरण के अनुरूप की जाएगी, अर्थात् :-

तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु 5100/- अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन तथा उच्च कार्यपालक श्रेणी	रु 6320/- अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो

टिप्पणी: (i) अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकती है जो किसी भी समय दी जाने वाली उपर्युक्त अधिकतम राशि की तीन गुणा से अधिक न हो, अथवा

(ii) वर्ष 2007 हेतु, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो माह अर्थात् नवंबर 2007 तथा दिसंबर 2008 हेतु आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस विनियम के उद्देश्य हेतु,

- जिन स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो उन सभी मामलों में अधिकारी के लिए 100% तथा उसके परिवार के सदस्यों हेतु 75% तक चिकित्सालयवास के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, अथवा
- 1 मई 2010 को अथवा बाद से, इस विनियम के अंतर्गत चिकित्सालय व्यय की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारियों हेतु द्विपक्षीय समझौता दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के अंतर्गत दिए गए चिकित्सालयवास योजना के नियम एवं शर्तों के अनुसार होगा, बशर्ते वे नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित सीमा के अधीन हो :-

तालिका

कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान (क) I तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II एवं III	(i) विस्तर शुल्क स्वयं - रु 700/- प्रति दिन परिवार - रु 525/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 125% के मान पर
वरिष्ठ प्रबंधन वेतनमान (ख) IV एवं V तथा उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI एवं VII	(i) विस्तर शुल्क स्वयं - रु 900/- प्रति दिन परिवार - रु 675/- प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों को लागू चिकित्सालयवास योजना के अंतर्गत दी गई सीमा का 150% के मान पर”;

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) हेतु, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के बावजूद, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 01 नवंबर, 2007 को तथा उसके बाद से, अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1.20% के बराबर राशि अथवा आवास के लिए मानक किराये का, इनमें जो भी कम हो, भुगतान करेगा :

परंतु जहाँ ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ बैंक द्वारा किसी अधिकारी से उसके वेतनमान, जिसमें वह रखा गया है, के प्रथम प्रक्रम के 0.25% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी :

परंतु यह भी कि जहाँ बैंक द्वारा ऐसी आवाज व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है वहाँ बिजली, पानी, गैस तथा सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे”।

10. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, उप विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) 01 मई 2010 से प्रभावी होने पर, 12 महीनों की समग्र अवधि के अंदर, अधिकतम 45 दिनों तक गर्भाशयोच्छेदन के मामले में अवकाश भी दिया जा सकता है”।

11. उक्त विनियमों की विनियम 41 में खंड (क) हेतु उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(क) विराम भत्ता - 01 मई, 2010 को तथा उसके बाद से, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में निर्धारित श्रेणी अथवा वेतनमान में अधिकारी, प्रतिदिन स्तंभ (2) में निर्धारित की गई दरों पर ‘विराम भत्ता’ पाने का हकदार होगा, अर्थात् :-

तालिका

अधिकारियों की श्रेणी/ वेतनमान	प्रमुख ‘ए’ वर्ग के नगर	क्षेत्र -1	अन्य स्थान
(1)	(2)		
	रु	रु	रु
वेतनमान IV तथा उससे ऊपर के अधिकारी	1000	800	700
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	800	700	600

लेकिन, वेतनमान IV तथा उनसे उच्च अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में बाहरी कार्य के दौरान प्रतिदिन रु 1200/- तथा वेतनमान I/II/III के अधिकारियों हेतु प्रतिदिन रु 1000/- की दर से विराम भत्ता देय होगा :

परंतु यह भी कि, यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम, किंतु 4 घंटे से अधिक है तो, ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण विराम भत्ता की संगणना हेतु - ‘प्रतिदिन’ का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि अथवा उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में रिपोर्ट करने के समय तथा अन्य मामलों में प्रस्थान के लिए निर्धारित समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो ‘प्रतिदिन’ का अभिप्राय होगा ऐसी अवधि जो 8 घंटे से कम नहीं है।”

12. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप विनियम (3) के बाद, निम्न लिखित उप-विनियमों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“(4) 01 मई, 2010 को या उसके बाद में, स्थानांतरण पर जाने वाला कोई अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, यात्री सामान के बीमा आदि से जुड़े व्यय के लिए नीचे दी गयी तालिका के अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र होगा, अर्थात् :

तालिका

श्रेणी	एकमुश्त राशि
उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन	रु.12,000
मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	रु.9,000

13. उक्त विनियमों के विनियम 44 में उप विनियम (3) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-

“बशर्ते कि 01 मई 2010 से प्रभावी, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान 1 में कोई अधिकारी, जो छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा रहा है, सबसे कम किराया अर्थव्यवस्था वर्ग में हवाई यात्रा करने का हकदार होगा, उस स्थिति में वास्तविक किराया या यात्रा की दूरी के लिए ट्रेन द्वारा ऐसी प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराया, जो भी कम है, की

प्रतिपूर्ति की जाएगी और समान नियम मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II व III के अधिकारी के लिए भी लागू होंगे, जो छुट्टी यात्रा रियायती का लाभ उठा रहा है, जहां यात्रा की दूरी 1000 किमी से कम है।'

14. उक्त विनियमों के विनियम 45 में -

- (i) उप विनियम (1) में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे अर्थात् :-
 "बशर्ते कि यह कि 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंकों की सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होगा।"
- (ii) उप विनियम (3) में खंड (ख) के बाद और टिप्पणी के पहले, निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :
 "(ग) अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत कवर किए गए अधिकारियों, जो पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं देते हैं, अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत जारी रहेंगे।"
- (iii) उप विनियमों (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :
 "(4) 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों को एक निश्चित अंशदायी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा, जहां अधिकारी 10% वेतन और महंगाई भत्ते का योगदान देगा तथा बैंक, भारत सरकार की अधिसूचना फा. सं. 5/7/2003-ईसीवी एवं पीआर दिनांक 22 दिसंबर, 2003 जैसा कि समय-समय पर संशोधित है, के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नई पेंशन योजना (एनपीएस) में, अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अनुसार समान राशि का योगदान देगा।"

15. उक्त विनियमों की अनुसूची के लिए, निम्न लिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 की अनुसूची

(विनियम 23 का उप-विनियम(2) देखें)

01 नवंबर, 2007 से एक अधिकारी, विशेष क्षेत्रीय भत्ता जो उसे वापस लेने तक या पूर्व या पाक्षिक रूप से संशोधन करने के समय तक, के लिए पात्र होगा तो तालिका में निम्नवत् दर्शाया गया है, जैसे :

तालिका

क्रम सं.	स्थान	भत्ते	
		रु 14,700/- से कम वेतन के लिए	रु 14,700/- से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
1.	मिजोरम (क) मिजोरम का चिंपतुईपुई जिला और मिजोरम के लुंगलाई जिले के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र	2000	2600
	(ख) मिजोरम के लुंगलाई शहर से 25 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लुंगलाई जिला	1600	2100
	(ग) मिजोरम का संपूर्ण आईजोल जिला	1200	1500
2.	नागालैंड	1600	2100
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (क) उत्तर एवं मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार एवं नारकोंडम द्वीप समूह	2000	2600
	(ख) दक्षिण अंडमान (पोट ब्लेयर सहित)	1600	2100

क्रम सं.	स्थान	भत्ते	
		रु 14,700/- से कम वेतन के लिए	रु 14,700/- से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	2000	2600
6.	असम	320	400
7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा (क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र (ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सारा त्रिपुरा	1600 1200	2100 1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश (क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र (ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सारा अरुणाचल प्रदेश	2000 1600	2600 2100
11.	जम्मू और कश्मीर (क) कठुआ जिला : नियावत बानी, लोही, मलहार और मछोडी	2000	2600
	(ख) उधमपुर जिला : (i) दुडु बसंतगढ़, लांडर भामाग इलाका, इनके अलावा जो भाग 2 (ख) में सम्मिलित थे। (ii) मोहरे तहसील के कंबन पक्ष से गोयल तक के क्षेत्र तथा कियासी पक्ष से अर्नास तक के क्षेत्र	2000 1600	2600 2100
	(ग) डोडा जिला : किश्तवार तहसील के नियावत नोगाम तथा पदेर के इलाके (घ) लेह जिला : जिले के सभी स्थान (ड) बारामुल्ला जिला : (i) संपूर्ण गुरेज-निरावत, तंगदर उप-मंडल तथा केरन इलाका (ii) मछिल (च) पूंछ तथा रजौरी जिला : पूंछ तथा रजौरी शहर और सुंदरबनी एवं दोनों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पूंछ तथा रजौरी जिले के क्षेत्र (छ) उपर्युक्त (क) से (च) में शामिल नहीं किए गए क्षेत्र किंतु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किमी की दूरी में आने वाले ऐसे स्थान जहां सीमा भत्ते के लिए राज्य सरकार द्वारा उनके कर्मचारियों को समय समय पर पात्र घोषित किया गया है।	2000 2000 2000 1600 1200 1200	2600 2600 2600 2100 1500 1500

क्रम सं.	स्थान	भत्ते	
		रु 14,700/- से कम वेतन के लिए	रु 14,700/- से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
12.	हिमाचल प्रदेश		
	(क) चंबा जिला		
	(i) पंगी तहसील, भामौर तहसील, पंचायत, वडगांव, वजोल, दओल कुगटी, नयागांव तथा टुंडा, गांव: जगत ग्राम पंचायत का घाटु, चौहाता ग्राम पंचायत का कनारसी	2000	2600
	(ii) भरमौर तहसील, उपर्युक्त मद (i) में शामिल गावों एवं पंचायतों को छोड़कर	1600	2100
	(iii) भटियात तहसील मे झांठु पंचायत ,डलहौजी शहर (वानीखेत सहित)	1200	1500
	(ख) किन्नूर जिला :		
	(i) असरंग,चितकुल और हांगों कूनो, चारंग पंचायत,छोटा खंभा,नाथपा और रूपी,पूह उप-मंडल की पंचायतों के आसपास के 15/20 क्षेत्र, ऊपर दिखाये गये पंचायत के क्षेत्रों को छोड़कर	2000	2600
	(ii) उपरोक्त (अ) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरे जिले	1600	2100
	(ग) कुल्लू जिला:		
	(I)खरगा,कुशवार और सर्गा ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए निर्मांड तहसील के 15/20 क्षेत्र .	2000	2600
	(II) बाहरी सरज (निर्मांड तहसील के जाकत-खाना और बरों गांवों को छोड़कर)	1200	1500
	(घ) लाहौल और स्पीती जिला :		
	लाहौल और स्पीती का पूरा क्षेत्र.	2000	2600
	(ड.) शिमला जिला:		
	(I)खूट,लाबाना-सादाना,सारपारा और चाडी-ब्रांडा पंचायतों को सम्मिलित करते हुए रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र .	2000	2600
	(II)डोरा-कावर तहसील,रामपुर मे डारकली ग्राम पंचायत,काशपथ तहसील और मुनीश,पारगना साराहन की घोरि चायविस.	1600	2100
	(III) चोपाल तहसील और घोरिस,पांजगांव,पत्सनाउ ,नौबिस और पर्गना साराहन के		

क्रम सं.	स्थान	भत्ते	
		रु 14,700/- से कम वेतन के लिए	रु 14,700/- से अधिक वेतन के लिए
1	2	3	4
	तीन कोटी, ताकलेश क्षेत्र की देहोथी ग्राम पंचायत, पारगाना बाराविस, कस्बा रामपुर और रामपुर तहसील की रामपुर परगना का घोरी नॉंग, शिमला शहर और इसके उपनगर (धाली, जाटोग, कासुमपति, मशोबरा, तारादेवी और टूटू)	1200	1500
	(च) कनगरा जिला: (I) बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल का क्षेत्र	1600	2100
	(II) कांगड़ा जिले के धरमशाला शहर और निम्नलिखित कार्यालय जो मुख्यालय की सीमा के बाहर स्थित हैं लेकिन धरमशाला शहर में शामिल हैं—महिला आईटीआई, दारी, यांत्रिक कार्यशाला, रामनगर, बाल कल्याण और शहर और देश नियोजन कार्यालय, सकोह, निचले सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगीयार, एचआरटीसी कार्यशाला, साधेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय कारखाने, दारी, आई.पी.एच. उप मंडल, डान, निपटान कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर, कांगड़ा जिले का एचपीकेवीवी परिसर को सम्मिलित करते हुए पालमपुर शहर और निम्नलिखित कार्यालय जो मुख्यालय की सीमा के बाहर स्थित हैं लेकिन धरमशाला शहर में शामिल हैं, एच.पी.कृषि विश्वविद्यालय परिसर, पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बानूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय //इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/एचपीपीडब्ल्यूडी मंडल, बुंदला, विद्युत उप-विभाजन, लोहना, डी.पी.ओ. निगम, बुंदला, विद्युत एचईएसईई प्रभाग, घुमगर.	1200	1500
	(छ) मंडी जिला: जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील में पंचायतें—बगरा, छतरी, छोटधार, गरगुशैन, गढ़, गर्यास, जंजेली, जारयार, जोहर, कालहानी, कालवान, खोलानल. लोथ, सिलिबागी, सोमचन, थच्छर, ताची, थाना, धरमपुर प्रखंड की पंचायतें—बिंगा, कमलह, सकलना, तानयार और तारखोलह, कसौंग तहसील की पंचायतें—बलिधर, बग्र, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुदी, मांज, पेखी, सैंज, साराहन और तेवान, सुंदर नगर तहसील की पंचायतें—बोही, बाटवारा, धन्यारा, पौरकोथि, सेरी और शोजा.	1200 1200	1500 1500
	(ज) सिरमौर जिला: बानी की पंचायतें, बाखली (पाछड़ तहसील), भारोग भेनरी (पओंत तहसील), बिरला (नाहम तहसील), दिव्वेर (पाछड़ तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) और थंस्गिरि ट्रैक्ट)	320	400
	(झ) सोलन जिला: मंगल पंचायत. (झ) हिमाचल प्रदेश के शेष इलाके जो उपरोक्त मद संख्या (अ) से (झ) तक में शामिल नहीं हैं.		
13	उत्तराखंड चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत क्षेत्र.	2000	2600"

विवरणात्मक ज्ञापन

जिन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है सदस्य बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट जनादेश के आधार पर भारतीय बैंक संघ और बैंकों के सुप्रीम स्तर के अधिकारियों के संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोटो और इस संबंध में सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार है। इसलिए ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एम. नागराजू, महाप्रबंधक(म.स.)
[विज्ञापन-III/4/असाधारण/92/18-19]

विशेष: उपरोक्त नियमों में पहले किए गए संशोधनों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अधिसूचित किया गया था।

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1	666/3/ए-1/292	29.07.1991
2	666/3/ए-1/424	22.02.1993
3	666/3/ए-1/179	20.05.1995
4	666/3/ए-1/1079	16.01.1997
5	666/3/ए-1/1318	18.03.1997
6	666/3/ए-1/529	04.11.1999
7	666/3/ए-1/393	25.07.2000
8	666/3/ए/223	10.07.2003
9	666/3/ए-1/908	27.01.2006
10	666/3/ए-1/1441	14.08.2006
11	666/3/20/आई आर/324	29.10.2011

ANDHRA BANK

(A Govt. of India Undertaking)

[Human Resource Department (IR)]

(HEAD OFFICE, HYDERABAD)

NOTIFICATION

Hyderabad, the 8th May, 2018

No. 666/3/20/IR/27.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1970), the Board of Directors of the Andhra Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Andhra Bank (Officers') Service Regulations, 1982, namely:—

- (1) These regulations may be called the Andhra Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2007, except as otherwise provided in these regulations.
- In the Andhra Bank (Officers') Service Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,—
 - for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(f) “family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), physically challenged brother or sister with forty per cent, or more disability and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer’.

Explanation.— For the purposes of this clause a child or parent or physically challenged brother or sister shall be deemed to be dependent on the officer if the monthly income of such child, parent, brother or sister does not exceed Rs.3,500 per month.

Provided that if the income of one of the parents exceeds Rs.3,500 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.3,500 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.’

(ii) Clause (o) shall be omitted.

3. In regulation 4 of the said regulations,—

(i) sub-regulation (4A) shall be omitted;

(ii) after sub-regulation (4A) as so omitted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) With effect from the 1st November, 2007, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.46800 – 1300/4 – 52000

Scale VI = Rs.42000 - 1200/4 – 46800

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.36200 – 1000/2 – 38200 – 1100/2 - 40400

Scale IV = Rs.30600 – 900/4 – 34200– 1000/2 – 36200

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.25700 - 800/5-- 29700 - 900/2 - 31500

Scale II = Rs.19400 - 700/1 - 20100 -800/10 - 28100

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.14500-600/7- 18700-700/2- 20100- 800/7-25700.

Explanation.—Every officer who is governed by the scales of pay in force as on the 31st October, 2007 shall be fitted in the scale of pay set out in this sub-regulation as on 1st November, 2007 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(6) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.”

4. In regulation 5 of the said regulations, —

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4, on and from the 1st November, 2007, the increments shall be granted subject to the following, namely:—

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (5) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II after reaching maximum of the higher scale shall be eligible for

four stagnation increments for every three completed years of service of which first two shall be Rs.800 each and next two Rs.900 each:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the second stagnation increment as on 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on 1st November, 2007 and another stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of second stagnation increment;

- (c) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service:

Provided that officers who have completed three years or more after receipt of the first stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the next stagnation increment with effect from the 1st November, 2007 and a subsequent stagnation increment on or after the 1st November, 2008 on their completion of six years after receipt of the first stagnation increment:

Provided further the officers appointed to or promoted in substantive Middle Management Grade Scale III, shall be eligible for four stagnation increments of Rs.900 each for every three completed years of service or :

Provided also that the officers who have already received two stagnation increments and completed more than three years of service after receipt of second stagnation increment as on the 1st November, 2007 shall get the third stagnation increment on the 1st November, 2007 and the fourth stagnation increment, on or after the 1st November, 2008 on completion of six years after receipt of second stagnation increment.

Explanation.— Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.

- (b) in sub-regulation (2),—
(i) in the Explanation, after clause (e) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

“(f) on and from the 1st day of November, 2007, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as under:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.410 per month after one year on reaching maximum of the Scale. (ii) Rs.1030 per month after two years on reaching maximum of the Scale;

Provided that an Officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that in a case where an officer, has already acquired any of the above qualifications and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account

of acquiring such qualification, he may be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st November 2007 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later.”;

(ii) in the Note, for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

“(v) if an officer, as on the 27th April 2010 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification, he shall be granted the Professional Qualification Pay, with effect from the 1st day of November, 2007 or the date of acquiring such qualification, whichever is later.”;

(c) in sub-regulation (3),—

(i) after clause (d) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

“(e) on and from the 1st November, 2007, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:—

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2007 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(A)	(B)	(C)
800	58	858
900	65	965
1000	72	1072
1100	79	1179
1200	86	1286
1300	94	1394”,

(ii) in the Note, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the Table under clauses (b), (c), (d) or (e) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (A) and (B) of the Table under clause (e) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4) or (5) of regulation 4 is earned.”;

(iii) clause (e) occurring after the Note shall be renumbered as sub-clause (v) thereof and for clause (v) as so numbered, the following clause be substituted, namely:—

“(v) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d) or (e) above, one year after reaching the maximum of the scale”;

5. In regulation 21 of the said regulations, —

(i) in sub-regulation (3), the Note shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (4), the Note shall be omitted;

(iii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation and Note shall be inserted, namely:—

- “(5) On and from the 1st day of November, 2007, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.15% of Pay.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation,—

- (a) “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments;
- (b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d), (e) and (f) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance’.
6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations(1) and (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(1)on and from the 1st day of November, 2002,

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(2)on and from the 1st day of November, 2007, —

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.20 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b)where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:—

TABLE

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(1)	(2)
(i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% of Pay

(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 1.20 per cent of Pay in the first stage of the Scale of Pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) above.

Note.— The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”;

7. In regulation 23 of the said regulations,—

- (i) in sub-regulation (1), for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (ii) in sub-regulation (2), for the figures, letters and words “1st day of November 2002, the figures, letters and words “1st day of November 2007” shall be substituted;
- (iii) for sub-regulations (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(3) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.290 per month or Rs.255 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of November, 2007, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.700 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of May, 2010, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.2300 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.1200 per month.”;

- (iv) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(8) on and from the 1st day of November 2007, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.165 per month.”;

- (v) in sub-regulation (10),—

(a) for the figures, letters and words “1st day of November 2002”, the figures, letters and words “1st day of November, 2007” shall be substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.550 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.680 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1570 per month”;

8. In regulation 24 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) Medical Expenses.- On and from the 1st day of November 2007, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:—

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.5100 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.6320 or the amount incurred whichever is less

Note.— (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above or;

(ii) for the year 2007, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2007 and December, 2007.

Explanation. — for the purposes of this regulation,—

- (i) hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100 per cent in the case of an officer and 75 per cent, in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization or;
- (ii) on and from the 1st day of May, 2010, reimbursement of hospitalisation expenses under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme as laid down under the Bipartite Settlement dated the 27th day of April, 2010 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:—

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.700 per day</p> <p>Family – Rs.525 per day</p> <p>(ii) Other charges</p> <p>At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	<p>(i) Bed Charges</p> <p>Self – Rs.900 per day</p> <p>Family – Rs.675 per day</p> <p>(ii) Other charges</p> <p>At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.”;</p>

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2007, a sum equal to 1.20 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.25 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 36 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

“(3) With effect from the 1st day of May 2010, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of 45 days.”.

11. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(a) Halting Allowance – On and from the 1st day of May, 2010, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to ‘per diem’ Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:—

TABLE

Grades/Scales of officers	Major 'A' Class cities	Area I	Other Places
(1)	(2)		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale IV and above	1000	800	700
Officers in Scale I/II/III	800	700	600

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, Halting Allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz., Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.1200 and for officers in Scale I or II or III, the per diem Halting Allowance and shall be Rs.1000:

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.— For the purpose of computing Halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.’.

12. In regulation 42 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) On and from the first day of May 2010, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:—

“TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.12,000
Middle Management and Junior Management	Rs.9,000”.

13. In regulation 44 of the said regulations, in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that with effect from the 1st May 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC First Class fare by train for the distance traveled, whichever is less and the same rules shall apply to an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kms.”.

14. In regulation 45 of the said regulations, —

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that there shall be no Provident Fund to Officers joining the services of the Banks on or after the 1st day of April, 2010.”;

(ii) in sub-regulation (3), after clause (b) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely: —

“(c) Officers who are covered under the Contributory Provident Fund Scheme who do not opt for Pension Scheme shall continue under the Contributory Provident Fund Scheme.”;

(iii) after sub-regulation(3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: —

“(4) The officers joining the services of the Bank on or after the 1st day of April 2010 shall be covered by a Defined Contributory Pension Scheme, where the officer shall contribute ten per cent, of pay plus Dearness Allowance and the Bank shall make the similar amount of contribution in accordance with the provisions of the Contributory Pension Scheme in accordance with New Pension Scheme notified by the Central Government vide notification of the Government of India, F.No.5/7/2003-ECB & PR dated the 22nd December, 2003, as amended from time to time.”

15. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely,:-

“Schedule to Andhra Bank (Officers’) Service Regulations, 1982

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2007, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
1.	Mizoram		
	(a) Chimpui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	2000	2600
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	1600	2100
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir		
	(a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District:		
	(i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District		
	(i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	2000	2600
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh		
	(a) Chamba District		
	(i) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(ii) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in item (i) above.	1600	2100
	(iii) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(b) Kinnaur District:		
	(i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(ii) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(c) Kullu District:		
	(i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of	2000	2600

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	Kharga, Kushwar and Sarga		
	(ii) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(d) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(e) Shimla District : (i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(f) Kangra District: (i) Areas of Bara Bhargal and Chhota Bhargal	1600	2100
	(ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	1200	1500
	(g) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil- of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gattoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500
	(h) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana	1200	1500

Sr. No.	Area	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.14,700/-	Pay above Rs.14,700/-
1	2	3	4
	Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract		
	(i) Solan District : Mangal Panchayat.	1200	1500
	(j) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (a) to (i) above.	320	400
13.	Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600"

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

M. NAGARAJU, General Manager (Hr)

[ADVT.-III/4/Exty./92/18-19]

Note: The amendments carried out earlier in the above Regulations were notified as per the details given below:—

S.No.	Notification No.	Date:
1.	666/3/A-1/292	29.07.1991
2.	666/3/A-1/1424	22.02.1993
3.	666/3/A-1/179	20.05.1995
4.	666/3/A-1/1079	16.01.1997
5.	666/3/A-1/1318	18.03.1997
6.	666/3/A-1/529	04.11.1999
7.	666/3/A-1/393	25.07.2000
8.	666/3/A/223	10.07.2003
9.	666/3/A-1/908	27.01.2006
10.	666/3/A1/1441	14.08.2006
11.	666/3/20/IR/324	29.10.2011